

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 771
No. 771

दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938
DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938

[रा.ग.स.क्र.दि. नं. 221
[N.C.T.D. No. 221]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

फा.स. एफ.10(13)/पर्याप्त/2015/2878-2900.—पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12.2015 के आदेशों का अनुपालन करते हुए, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्याप्त/6167-6189 दिनांक 20.10.2015, अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्याप्त/6345-6372 दिनांक 30.10.2015, अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्याप्त/7400-7422 दिनांक 23.12.2015, संशोधित अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्याप्त/99-130 दिनांक 05.01.2016 एवं एफ.10(13)/पर्याप्त/2015/436-468 दिनांक 21.01.2016, अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्याप्त/2015/1049-1072 दिनांक 16.02.2016 और अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्याप्त/2015/1610-1632 दिनांक 04.03.2016 के अनुक्रम ने तथा पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियन्त्रण) प्राधिकरण की दिनांक 10.03.2016 की बैठक के कार्यवृत्त के निर्देशों के अनुसरण में निम्नलिखित निर्णय अधिसूचित किए जाते हैं:—

- घटना के तुरन्त बाद पुलिस नियन्त्रण कक्ष संख्या—100 पर टोल एकत्रकर्ता उल्लंघन करने वाले वाहन के गाड़ी संख्या को बताएगा, जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) लगाने वाले अधिसूचना का अनुपालन नहीं करता है।
- संबंधित थाने में टोल एकत्रकर्ता एक प्राथमिक दर्ज कराएगा और पुलिस जल्द से जल्द उस पर लचित कार्यवाली करेगी।
- यदि कोई वाहन ई.सी.सी. के बिना भुगतान/गैर गतिव्य दिल्ली के/2006 से पूर्व के पंजीकृत पाया जाता है तो, उस समय लग्न पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार का दर युना चुम्बन लगाया जाएगा। तीन बार से अधिक अनाधिकृत प्रवेश करने वाले प्रत्यक्ष वे वाहन को न्यूनतम एक गहर की अवधि के लिए जल्द कर लिया जाएगा और वाहन को पंजीकरण प्रभार पर भिन्न ही दर दिया जाएगा।

युलानद नामी निशेष नियम (प्रयोगस्थ)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 26th April, 2016

No. F.10(13)/Env/2015/2878-2900.—In continuation of notification No. F10 (13)/Env/2015/6167-6189 dated 20.10.2015, notification no. F10 (13)/Env/2015/6345-6372 dated 30.10.2015, notification no. F10 (13)/Env/2015/7400-7422 dated 23.12.2015, amendment notification no. F10 (13)/Env/2015/98-130 dated 05.01.2016, notification no. F10 (13)/Env/2015/436-458 dated 21.01.2016, notification no. F10 (13)/Env/2015/1049-1072 dated 15.02.2016 and notification no. F10 (13)/Env/2015/1610-1632 dated 04.03.2016 issued by Department of Environment, Govt. of NCT of Delhi in compliance of the Hon'ble Supreme Court's orders dated 09.10.2015 and 16.12.2015 regarding Environment Compensation Charge (ECC) and in pursuance of directions of the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA) as per minutes of meeting held on 10.03.2016 the following decisions are hereby notified :

1. The toll collector shall flash the vehicle number of the violator, who do not comply with notifications on levy of Environment Compensation Charge, on Police Control Room No. 100 immediately after the incident.
2. The toll collector shall file a FIR at the concerned police station and the police shall take appropriate action at the earliest.
3. If a vehicle is caught either without paying ECC/ non-destined to Delhi/ pre-2006 registered, then a fine of 10 times of the applicable ECC shall be imposed. In case the offence of unauthorized entry is committed more than three times, the vehicle shall be impounded for a minimum period of 01 month and the Registration Certificate of the vehicle will be suspended.

KULANAND JOSHI, Sp. Secy. (Environment)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

सं0फा0 ८/५८/२००२/डीआईएसएमएच/प्रशा०/१३५६—गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24.७.१९६८ के कार्यालय इापन संख्या 24/७८/६८—डीएच (एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत बदल विकल्पों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित सामान्य इयूटी विकित्सा अधिकारी (भारतीय विकित्सा पद्धति) नियमावली, 2012 के दिल्ली स्वास्थ्य सेवा नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के सभी पूर्व पठनकर्ता के पश्चात् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आयुष निदेशकालय ने सामान्य इयूटी विकित्सा अधिकारी (भारतीय विकित्सा पद्धति) दिल्ली स्वास्थ्य सेवाएं नियमावली बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** — (1) इन नियमों को सामान्य इयूटी विकित्सा अधिकारी (भारतीय विकित्सा पद्धति) दिल्ली स्वास्थ्य रोना नियमावली, 2016 कहा जाए।।।
(2) सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से यह लागू होंगे।
2. **परिभाषाएं** :— जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन नियमों में —
(क) "आयोग" का अर्थ संघ लोक सेवा आयोग से है,
(ख) "नियंत्रक प्राधिकरण" का अर्थ स्वास्थ्य एवं परिषर कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है,
(ग) "विभागीय पदोन्नति समिति" का अर्थ सेवा के कांवर्ग के पदों की पदोन्नति या स्थायीकरण के बहली तर दिनांक डेंट्र चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट के वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति से है,
(घ) "इयूटी पद" का अर्थ किसी उस यद से है जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट चाहे यह स्थार्ट का अन्तर्गत है।
(ङ) "सरकार" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद २३९ के अन्तर्गत राष्ट्रपति हाथ नियुक्त एवं अनुच्छेद २३९ का का अन्तर्गत यथा पदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है।
(ज) "ग्रेड" का अर्थ प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रेडों में से किसी एक ग्रेड से है,
(छ) "अनुसूची" का अर्थ इन नियमों के साथ सलग किसी अनुसूची से है,
(ज) "सेवा" का अर्थ दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य इयूटी विकित्सा अधिकारी भारतीय विकित्सा से है।